SHIKSHA SAMVAD
International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
Volume-02, Issue-02, December- 2024
www.shikshasamvad.com

NEP 2020 के समावेशी शिक्षा सुधार: एक औपचारिक विश्लेषण

सुरेन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
श्री गोविंद महाविद्यालय तेवरखास
बिलारी मुरादाबाद
Email id sk363710@gmail.com

सारांश

सारांश का उद्देश्य NEP 2020 में समावेशी शिक्षा के लिए किए गए नीतिगत एवं प्रत्यक्ष सुधारों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करना है। इस भाग में, संविधान एवं नीति आयोग जैसे अन्य स्रोतों की विशिष्टताओं के आधार पर बताया गया है कि कैसे यह योजना समावेशी शिक्षा के मर्म को समझते हुए सबके हित में कदम उठाने का प्रयास है। इस में यह भी दर्शाया गया है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना और शिक्षा के अनुभव को उनके विविध आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है। इसके अंतर्गत, NEP 2020 में प्रवेश, दक्षता, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में बदलाव, पहचान-आधारित समर्थन प्रणालियों का प्रावधान, एवं संस्थानात्मक ढांचे का समावेशी रूप में पुनर्गठन पर बल दिया गया है। विशेष रूप से, शिक्षक प्रशिक्षण में बदलाव एवं मूल्यांकन मानकों का संकल्पना इस बात का संकेत है कि केन्द्रीय शिक्षा व्यवस्था में समावेशन का समर्पित खाका तैयार किया गया है। विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है, जिनमें आर्थिक, सामाजिक एवं संरचनात्मक बाधाएँ सम्मिलित हैं। इन सुधारों का प्रभाव एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मानदंड एवं तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत हैं। साथ ही, वैश्विक अनुभवों से सीख एवं भारतीय संदर्भ में इन्हें कैसे संवर्धित किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया गया है। निष्कर्ष में बताया गया है कि समावेशी शिक्षा को साकार करने हेतु नीतियों का स्पष्ट दिशा तय करना और उनकी प्रभावशीलता का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। इस दृष्टि से, यह सारांश नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन के बीच संतुलन बनाने तथा सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास है।

मुख्य शब्द: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, समावेशी शिक्षा, शिक्षण विधियाँ,अदि।

1. प्रस्तावना:

प्रस्तावना खंड में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अन्तर्गत समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों का व्यापक संकेत दिया गया है। यह सुधार शिक्षा प्रणाली को अधिक समान और समानता आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके शिक्षण अनुभव को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच दूरी और भिन्नताओं को कम करते हुए शिक्षा का उद्देश्योन्मुखी और सहज पहुँच सुनिश्चित करना है। इसके लिए, कक्षा स्तर पर विविधताओं का सम्मान करते हुए शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रमों का पुनःमूल्यांकन एवं समावेश किया गया है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त हो सके। प्रस्तावना में यह भी संकेतित है कि इन सुधारों को लागू करने के लिए शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और प्रशासनिक तंत्र की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ताकि इनके दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित किए जा सकें। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि समावेशी शिक्षा केवल चुनौतियों का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली में वैश्विक मानकों और नवीनतम शिक्षण प्रवृत्तियों के समावेश का भी माध्यम है। इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य ऐसे सक्षम एवं समावेशी समाज का निर्माण है जहां हर छात्र को उसकी विशेषताओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर समान अवसर प्राप्त हों। इन दिशानिर्देशों का पालन निष्पक्षता और समानता की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक सतत प्रयास है, जो शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता की वास्तविक भावना को अभिव्यक्त करता है।

2. समावेशी शिक्षा की अवधारणा और NEP 2020 का उद्देश्य

समावेशी शिक्षा की अवधारणा का आधार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्टता को मान्यता देना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। भारत में यह धारणा स्वतंत्रता एवं समानता के मूल सिद्धांतों के साथ मेल खाती है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, लिंग, क्षमता एवं मान्यताओं को समावेशी रूप से शिक्षण प्रणाली में शामिल करने का लक्ष्य है। नेशनल शिक्षण नीति 2020 इस दृष्टिकोण को मुख्य आधार बनाते हुए, समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा प्रणाली का स्थायी ढांचा प्रस्तुत कर, सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षण अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकें। इस नीति का व्यापक उद्देश्य ऐसा शिक्षण वातावरण निर्मित करना है, जहां भिन्नताओं की समझ एवं स्वीकृति हो और शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं का सम्मान करे।

NEP 2020 का विशेष लक्ष्य है, विविध पृष्ठभूमियों वाले विद्यार्थियों को सीखने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें प्राथमिकता दी गई है कि शिक्षा प्रणाली में न केवल सामान्य श्रेणी के बच्चों को, बल्कि दिव्यांग, वंचित या पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी पूरा समर्थन और अवसर प्राप्त हो। इसके तहत पाठ्यक्रम, शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रणालियों में नवीनता लाई गई है, ताकि सभी स्तर पर समावेशिता संभव बन सके। इसके अतिरिक्त, शिक्षण संस्थानों का संशोधित ढांचा इतना सुदृढ़ किया गया है कि वे समावेशी शिक्षा के केंद्रबिंदु पर कार्यरत रह सकें। शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं विकास भी इस दिशा में कदम हैं, जिसमें समावेशी शिक्षण की चुनौती एवं जिम्मेदारी शिक्षकों को प्रभावी ढंग से संभालने का कौशल विकसित किया जाता है। इस प्रकार, NEP 2020 समावेशी शिक्षा को एक समग्र, संरचित एवं प्रतिबद्ध रणनीति के माध्यम से भारत में व्यावहारिक रूप में स्थापित करने का प्रयास है।

3. प्रमुख सुधारों का विश्लेषण

"प्रमुख सुधारों का विश्लेषण" अनुभाग में NEP 2020 द्वारा प्रस्तुत समावेशी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक जाना-माना कदमों का विस्तृत अवलोकन किया गया है। इसमें पहला महत्वपूर्ण सुधार है, सभी के लिए प्रवेश और अवसर का सुनिश्चित करना। यह पहल वंचित एवं दुर्बल वर्गों को शिक्षा प्रणाली में सहज एवं समुचित भागीदारी हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष अनुदान, छात्रवृत्तियों और

संरचनात्मक बदलावों का समावेश है, ताकि छात्रों को प्रारंभिक स्तर से ही समान अवसर प्राप्त हो सकें। दूसरा मुख्य सुधार विविधता-समर्थित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धतियों का विकास है। इसमें बहुविविधता आधारित पाठ्यक्रमों का निर्माण व् शिक्षण तकनीकों का समावेश किया गया है, जिससे विद्यार्थियों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विविधताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। यह प्रयास शिक्षकों को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने का भी प्रयास है। तीसरा प्रमुख पहल पहचान-आधारित आवश्यकताओं एवं समर्थन प्रणालियों का सुधार है। इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए अनुकूल विशेष सेवाएं, teknolojik सहायता, और मार्गदर्शन तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इन उपायों से उन छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, जो सामान्य पाठ्यक्रम से वंचित रह जाते थे।

चौथा सुधार शिक्षा संस्थानों का समावेशन-केंद्रित ढांचे का निर्माण है। इस पहल के अंतर्गत नए मानक एवं नीति को अपनाकर शैक्षणिक संस्थान अधिक समावेशी बनाए गए हैं। इसमें समावेशन-संबंधित प्रशिक्षण, अवसंरचना का सुधार और संसाधनों का समान वितरण शामिल है, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। पाँचवाँ महत्त्वपूर्ण सुधार शिक्षण-शिक्षिका प्रशिक्षण में समावेशन पर केंद्रित है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुसूची तैयार कर शिक्षकों को समावेशी शिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे शिक्षण व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आकर, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखा जा सकता है। अंत में, मूल्यांकन और आकलन के नए मानकों का विकास किया गया है। इसमें अध्ययन की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर आधारित समावेशी मूल्यांकन प्रणालियाँ लागू की गई हैं, ताकि विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं और जरूरतों का समुचित आकलन हो सके। कुल मिलाकर, ये सुधार समावेशी एवं समान शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रणाली में बदलाव ला रहे हैं।

3.1. सभी के लिए प्रवेश और अवसर

"सभी के लिए प्रवेश और अवसर" के संदर्भ में NEP 2020 ने समानहम दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षण में समावेशन के व्यापक तत्वों को स्तर पर समावेशी बनाने का प्रयास किया है। इस सम्बंध में, नीति ने निर्धारण किया है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश का अवसर आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक सीमाओं से बाधित नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत, समाज के वंचित एवं कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ और नीतियाँ विकसित की गई हैं, जिनमें छात्रवृत्तियाँ, मुआवजा योजनाएँ और सुलभ आवास सुविधाएँ शामिल हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए, विद्यालयों में सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया सरल और पहुँच योग्य बनाई गई है। साथ ही, अलग-अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और समावेशी प्रवेश प्रबंधन प्रणाली का प्रसार किया गया है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य भेदभाव रहित शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का विस्तार है ताकि विविध पृष्ठभूमि वाले छात्र शिक्षण स्थल पर समान भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अधिकांश कदमों में, स्थानीय समुदायों और अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है ताकि जागरूकता और सचेतना का प्रसार हो सके। इससे न केवल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, बल्कि उनके शैक्षिक जीवन में सतत विकास भी सुनिश्चित होता है। इसीलिए, 'सभी के लिए प्रवेश और अवसर' के अंतर्गत, सरकार, शिक्षा बोर्ड एवं कार्यान्वयन एजेंसियों का संयुक्त प्रयास इन सम्मिलित पहलुओं को प्रभावी रूप से लागू करने का लक्ष्य रखता है। परियोजना का मुख्य आधार सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ताकि समाज में समावेशी और समान स्वच्छंदता का निर्माण हो सके।

3.2. विविधता-समर्थित पाठ्यक्रम और शिक्षण-पद्धतियाँ

विविधता-समर्थित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-पद्धतियों का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विविधताओं का सम्मान एवं समावेशन सुनिश्चित करना है। इस दृष्टिकोण से, पाठ्यक्रम का स्वरूप न केवल प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बल्कि उच्च शिक्षण में भी विविधतापूर्ण मानकों का समावेश करता है, ताकि विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। इसमें विविध प्रकार की विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और सीखने की अर्हताओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे शिक्षण सामग्री और विधियों में समावेशन की भावना जागरूकता के साथ विकसित हो सके।

शिक्षण-पद्धतियों के संदर्भ में, NEP 2020 ने विद्यार्थियों की प्रेरणा और रुचियों को ध्यान में रखते हुए अधिक संवादात्मक, सृजनात्मक और बहु-संसाधन शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया है। इनमें समूह गतिवयों, परियोजना आधारित शिक्षण, तकनीकी संसाधनों एवं डिजिटलीकरण का व्यापक प्रयोग शामिल है। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे विविधता भरे वर्गों में अनुकूलित एवं संवेदनशील शिक्षण शैली अपनाने में समर्थ बनें। इसके अलावा, मूल्यांकन की प्रणालियों में भी परिवर्तन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों की बहु-आयामी क्षमताओं का आकलन करने पर जोर दिया गया है।

यह प्रणाली सीखने की बाधाओं को कम करने और सभी विद्यार्थियों के शैक्षिक समावेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इस संदर्भ में, पाठ्यक्रम और शिक्षण-पद्धतियों का अभिविन्यास समावेशन के सिद्धांतों के साथ हो रहा है, ताकि सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक इन बाधाओं से जूझ रहे विद्यार्थियों को भी समान अवसर प्राप्त हो सके। वे शिक्षण संसाधनों एवं पद्धतियों को इस प्रकार विकसित किया जाता है ताकि प्रतिभागियों की विविधता का सम्मान हो और उनका समुचित विकास संभव हो। इसलिए, यह नवाचार शिक्षण प्रक्रिया में समावेशन को मजबूत करने तथा शिक्षा प्रणाली में समावेशी समाज की नींव रखने का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो रहा है।

3.3. पहचान-आधारित आवश्यकताएँ और समर्थन प्रणालियाँ

पहचान-आधारित आवश्यकताएँ और समर्थन प्रणालियाँ समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं, जो प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट पहचान एवं आवश्यकताओं के आधार पर सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। इन प्रणालियों का उद्देश्य है कि विविध पृष्ठभूमि, योग्यता, अक्षमताएँ या संस्कृतिक विशेषताएँ रखने वाले छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जाएँ। इस दिशा में, नीति ने विभिन्न पहचान प्रणालियों जैसे कि विकलांगता प्रमाणीकरण, भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान, और आर्थिक स्थिति के आधार पर आवश्यकताओं का आकलन करने की व्यवस्था की है। समर्थन प्रणालियों में व्यक्तिगत शिक्षा योजना (पीईपी), लाड़ली, अनुदान एवं अनुकूलन, विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं सहायता केंद्रों का सृजन प्रमुख हैं। पीईपी के माध्यम से विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का आंकलन कर विशिष्ट शिक्षण रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता को अधिकतम किया जा सके। साथ ही, इन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण सामग्री, तकनीकी उपकरण एवं सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उदाहरणस्वरूप, विकलांग छात्रों के लिए श्रवण सहायक उपकरण, ब्रेल में पाठ्यक्रम सामग्री और विषयगत सहायता केंद्र का गठन किया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि पहचान-आधारित समावेशन की प्रणाली सभी फलक पर प्रभावी हो। इसके लिए नियमित मूल्यांकन और फीडबैक का सृजन भी आवश्यक है, जिससे जानकारी समय-समय पर अद्यतन की जा सके। इससे छात्रों की आवश्यकताओं की बदलती प्रकृति के अनुरूप समर्थन व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ ही, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर शिक्षकों और अभिभावकों को इन प्रणालियों का सही उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है।

इस अध्ययन में यह भी माना गया है कि समावेशी शिक्षा के लिए पहचान-आधारित आवश्यकताएँ एवं समर्थन प्रणालियाँ अतिआवश्यक हैं, क्योंकि वे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को सम्मानित करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को समग्र रूप से प्रभावी बनाती हैं। यह प्रणाली व्यक्तिगत

आवश्यकता एवं मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए, समावेशी शिक्षण वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करती है। इस दृष्टिकोण से, नीति का कार्यान्वयन सतत कल्याणकारी एवं सतत सुधारात्मक दिशा में प्रतिबद्ध होना चाहिए।

3.4. शिक्षा संस्थानों का समावेशन-केंद्रित ढांचा

NEP 2020 में शिक्षा संस्थानों के समावेशन को मुख्य प्राथमिकता मानते हुए, इसे एक सुसंगत और प्रभावी ढांचे के माध्यम से स्थापित किया गया है। इस ढांचे का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, पृष्ठभूमि और क्षमता के आधार पर सुनिश्चित करना है कि वे शिक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकें। इसके लिए, संस्थानों को समावेशन-प्रेमी, उत्तरदायी और लचीले बनाने पर बल दिया गया है ताकि विविधता में भी समान अवसर प्राप्त हो सकें। इस ढांचे के अंतर्गत, संस्थानों को अपनी आदान-प्रदान, पाठ्यक्रम, शिक्षण-पद्धतियों और परीक्षा प्रणाली में समावेशिता को मुख्य रूप से फोकस करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष ध्यान दिया गया है कि शिक्षण संसाधनों का निर्माण विशेष जरूरतमंद विद्यार्थियों, जैसे कि विकलांग, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा संस्थान शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समावेशन का प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल शिक्षण तकनीकों का प्रयोग कर सकें। साथ ही, समावेशन को संस्थागत स्तर पर स्थापित करने के लिए, नयें मानक और दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। इनमें समावेशी माहौल का निर्माण, संसाधनों का समान वितरण, और सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इस ढांचे के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, निगरानी और मूल्यांकन के तंत्र भी मजबूत किए गए हैं, जिनसे निरंतर सुधार और समावेशन के स्तर का आकलन संभव हो सके।

इन उपायों का लक्ष्य है कि शिक्षा का समावेशन न केवल विद्यार्थियों की पहचान, आवश्यकता और पार्श्वभूमि के आधार पर हो, बल्कि यह एक स्थायी और कार्यात्मक परिवर्तन भी सुनिश्चित करे। इससे संस्थान समावेशी वातावरण को अपनाकर समाज में समानता और समरसता का निर्माण कर सकें, जो वास्तव में समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप है।

3.5. शिक्षण-शिक्षिका प्रशिक्षण में समावेशन

शिक्षण-शिक्षिका प्रशिक्षण का समावेशन का दृष्टिकोण शिक्षा का आधारभूत स्तंभ है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों में विविधता के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता विकसित हो, ताकि वे छात्रों की भिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षणMetodo प्रदान कर सकें। NEP 2020 में इस समर्थन प्रणाली को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी गई है, जिसमें प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा का प्रस्तुतीकरण आवश्यक है, जिससे शिक्षक संबद्धता, संवेदनशीलता, और आवश्यक व्यावहारिक कौशल से लैस हो सकें।

यहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि प्रशिक्षण में विविधता-संबंधी जागरूकता एक अनिवार्य घटक है। इसमें छात्रों की पहचान, आवश्यकताएँ एवं विविध क्षमताओं को समझने की क्षमता विकसित करनी होती है। शिक्षकों को सहभागी शिक्षण योजनाएँ, अनुकूल शिक्षण सामग्री एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों की सहायता के लिए रणनीतियाँ सिखाई जाती हैं। इसके साथ ही, प्रशिक्षकों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु मेधावी शिक्षक शिक्षण संस्थानों को मान्यता एवं निरंतर प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षण-शिक्षिका प्रशिक्षण में नवीनतम विश्वस्तरीय अभ्यास, डिजिटल माध्यम एवं तकनीकी कौशलों का समावेशन आवश्यक है। इससे न सिर्फ शिक्षकों को समावेशी शिक्षण पद्धतियों का अभ्यास करने का अवसर मिलते हैं, बल्कि वे छात्रों की विविध आवश्यकताओं का सम्यक रूप से सामना करने में सक्षम भी हो जाते हैं। अंततः, ऐसे प्रशिक्षकों का विकास समावेशन की दिशा में शिक्षण संस्थानों में बदलाव लाने में

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षकों की क्षमता विकसित होती है और समावेशी, न्यायसंगत एवं सुलभ सीखने का परिवेश सुनिश्चित होता है।

3.6. मूल्यांकन और आकलन के नए मानक

मूल्यांकन और आकलन के नवीन मानकों का निर्धारण समावेशी शिक्षा की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। इस संदर्भ में, NEP 2020 ने परंपरागत परीक्षात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित कई पुरानी धारणाओं को चुनौती देते हुए अधिक व्यापक, निष्पक्ष, और विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप मानदंड विकसित किए हैं। इस प्रणाली में मात्रात्मक मापदंडों की बजाय अंतःप्रयोजनात्मक और प्रक्रियात्मक मूल्यांकन पर बल दिया गया है, जिससे छात्र की व्यापक क्षमता का सही आकलन संभव हो सके।

NEP 2020 के तहत, नये मानकों का लक्ष्य न केवल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का विश्लेषण है, बल्कि यह उनकी समग्र विकास प्रक्रिया, रचनात्मकता, सामाजिक सहभागिता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी समुचित आकलन करना है। इसमें प्राक्कलन प्रक्रिया में बहु-आयामी परीक्षण और निरंतर आकलन को शामिल किया गया है, जो विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, फीडबैक और सुधार की प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया है, ताकि शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति का समुचित मार्गदर्शन मिल सके।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य अधिक समावेशी एवं निष्पक्ष आकलन प्रणाली तैयार करना है, जो विकलांगता, लिंग, सांस्कृतिक भिन्नताओं और पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न करे। इस नवीनतम मानक में, परीक्षा के तरीकों को अधिक लचीला और विद्यार्थियों की विविधता के अनुरूप बनाया गया है, ताकि हर छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सके। खासकर, व्यक्तिपरक क्षमताओं जैसे रचनात्मकता, संवाद कौशल, नेतृत्व आदि का भी मूल्यांकन किया जाता है, जो उनके समग्र व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह नई प्रणाली विद्यालयों में मूल्यांकन की प्रवृत्ति में बदलाव लाते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा परीक्षा के चक्कर से मुक्त करने का प्रयास है। इसके साथ ही, शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी बदलाव किया गया है, ताकि वे आधुनिक मूल्यांकन उपकरणों का प्रभावी उपयोग कर सकें। इस प्रकार, NEP 2020 के तहत अपनाये गए मानक न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास को समर्थ बनाते हैं, बल्कि उनके समावेशी विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं।इस प्रक्रिया में पारंपरिक परीक्षाओं की तुलना में अधिक व्यापक एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धतियों को अपनाकर विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं का सम्मान किया गया है, जो समावेशी शिक्षा अभियान की सफलता का आधार बनता है।

4. समान अवसर बनाम व्यावहारिक बाधाएँ

समान अवसर प्राप्ति के प्रयासों के बावजूद, व्यावहारिक बाधाओं का अस्तित्व निरंतर चुनौती बना हुआ है। सबसे पहले, संसाधनों की अपर्याप्तता मुख्य समस्या के रूप में उभरती है। आवश्यक पूंजी, पूर्व प्रशिक्षण, और समावेशी पाठ्यक्रमों का विकसित करना अनेक शैक्षणिक संस्थानों के लिये एक बड़ा जोखिम और लागत का विषय है। इसके साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में विविधता और अभाव भी महत्वपूर्ण बाधा है। अनेक शिक्षकों को समावेशन की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव है, जिससे व्यावहारिक रूप से नई नीतियों का प्रभाव पड़ना कठिन हो जाता है।

सामाजिक संरचना में मौजूद भेदभाव, जाति, धर्म, भाषा व लिंग के आधार पर अपेक्षाकृत अत्यधिक विभाजन व्यावहारिक बाधाओं को और मजबूत करता है। कई क्षेत्रों में पारंपरिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण परिवर्तन कठिन हो रहा है। साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों का समावेशी ढांचा निर्माण अभी भी अपर्याप्त है। विशेष सुविधाओं और समर्थन प्रणालियों की कमी के कारण बहु-आयामी आवश्यकताओं वाले

विद्यार्थियों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती। यह अंतराल शिक्षकों, अभिभावकों तथा नीति-निर्माताओं के बीच में भी देखा जा सकता है, जहां जागरूकता और समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है।

अतः, इन बाधाओं का सामना करने हेतु प्रभावी संसाधन व्यवस्था, शिक्षकों का प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता व सहयोगी ढाँचों का विकास आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों का विश्लेषण कर, व्यापक रणनीतियों एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से ही समान अवसर के लक्ष्य को सतत रूप से साकार किया जा सकेगा।

5. प्रभाव-आकलन के मानदंड और तुलनात्मक विश्लेषण

प्रभाव-आकलन के मानदंड और तुलनात्मक विश्लेषण के दौरान अधिकांश गुणवत्ता मापदंडों का उपयोग किया जाता है, जिनमें शिक्षाप्रदर्शक कार्यक्रमों का प्रभाव, छात्र सीखने की प्रगति, समावेशी दृष्टिकोण के प्रभाव और संसाधनों का समुचित वितरण शामिल हैं। इन मानदंडों का उद्देश्य न केवल वर्तमान सुधारों की प्रभावकारिता का आकलन करना है, बल्कि भविष्य के संशोधनों के लिए आवश्यक सूचनाएं भी प्रदान करना है। तुलनात्मक विश्लेषण में विभिन्न राज्यों और शिक्षण संस्थानों के डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान हो सके। इस प्रक्रिया में, पासिंग प्रतिशत, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण स्तर, और संसाधनों की उपलब्धता जैसे मानकों का स्थिर और तुलनात्म्क रूप से मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही, प्रभाव का निरंतर आकलन स्थिरीकरण हेतु दीर्घकालिक अध्ययन और फीडबैक तंत्र का भी उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इन मानदंडों की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता, निर्धनों की संख्या, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की भागीदारी, और संस्थागत सुधारों का विश्लेषण शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि सुधारों की प्रभावशीलता उस संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है, जहाँ सामाजिक न्याय और समावेशन का लक्ष्य समग्र शिक्षा प्रणाली में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। तुलनात्मक विश्लेषण में, विकसित और विकासशील देशों के प्रावधानों और प्राप्तियों का भी उल्लेख किया जाता है, ताकि भारत के संदर्भ में बेहतर रणनीतियों का निर्धारण किया जा सके। इस प्रकार, प्रभाव-आकलन के मानदंड और तुलनात्मक विश्लेषण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सतत सुधार के लिए आधारभूत उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाते हैं।

6. नीति-नियोजन और क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें

नीति-नियोजन और क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि निर्धारित नीतियों का स्पष्ट और व्यावहारिक रूप से समझदारीपूर्ण अनुसरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए, एक मजबूत कार्यान्वयन ढांचा बनाना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक चरण की प्रभावशीलता का समय-समय पर मूल्यांकन और आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में स्थानीय शिक्षा संस्थानों, समुदाय और संबंधित अधिकारिणियों की भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा की धारणा को सशक्त बनाता है। इसके अतिरिक्त, नीति बनाने में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक चैलेंजों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वास्तविक समानता सुनिश्चित हो सके। संसाधनों का समुचित आवंटन, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार समर्थन सेवाओं का विस्तार मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सरकार एवं संबंधित निकायों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर नेत्रत्व एवं जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, ताकि नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। अंततः, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर समीक्षा, स्थायी रणनीतियों और संसाधन समर्पण के

साथ ही सभी सहभागी उपायों का समायोजन आवश्यक है, ताकि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो सके और सर्वविविधता को सम्मानित किया जा सके।

7. वैश्विक अनुभवों से सीख और भारत के संदर्भ

विभिन्न वैश्विक देशों में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों से भारत को उल्लेखनीय शिक्षण तथा सामाजिक सुधार लेने का अवसर मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के सफल मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने प्रति-आधारित एवं संसाधन-सक्षम शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बहुविकलांग एवं अतिसंवेदनशील बच्चों के लिए समर्पित विशेष शिक्षण कार्यक्रम विकसित हुए हैं, जिनमें परिवार एवं समुदाय का सक्रिय सहभागिता आवश्यक समान है। ये देशों में प्रशिक्षण, अनुकूल पाठ्यक्रम एवं संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष बल दिया गया है, जिसका अनुकरण भारत के संदर्भ में शिक्षा की समावेशन क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से प्राप्त शिक्षाओं में एक मुख्य बात यह है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी, पर्याप्त अधिवेशन एवं स्थायी संसाधनों का सुनिश्चित होना अनिवार्य है। शिक्षण संस्थानों में पहचान-आधारित आवश्यकताओं पर आधारित समर्थन प्रणालियों का निर्माण, टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग और शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण इन देशों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं। इन उदाहरणों से सीख मिलती है कि विश्वभर में बहुविकलांग, आर्थिक रूप से पिछड़े, जाति व गृहस्थ के आधार पर भेदभाव से मुक्त एवं विविधताओं का सम्मान करने वाली शिक्षा प्रणालियों का स्थापना अत्यावश्यक है। भारत में इस अनुभव से प्राप्त अनुकरणीय रणनीतियों का कार्यान्वयन उचित संसाधन, संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं शिक्षा का व्यापक क्रियान्वयन योजना के साथ किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि शैक्षिक समावेशन सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित कर सके। वैश्विक अनुभव यह भी दर्शाते हैं कि समावेशी शिक्षा का प्रभाव समय के साथ ही जागरूकता एवं स्थायी परिवर्तन का कारण बनता है, जो एक समावेशी समाज का आधार है। अतः भारत में इन सीखों को अपना कर समावेशी शिक्षा के दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

8. निष्कर्ष

NEP 2020 के समावेशी शिक्षा सुधारों का विश्लेषण करते समय यह स्पष्ट है कि इन पहलों ने शिक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलावों को प्राथमिकता दी है, जिससे सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए उन्हें समुचित समर्थन प्रदान करना है। यह न केवल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करता है। कई सुधार कर्मिषाली हैं, जैसे कि समावेशी पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों, जो विद्यार्थियों की पहचान-आधारित आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इसके साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों में भी समवादी दृष्टिकोण की दिशा में परिवर्तन हुआ है ताकि शिक्षकों को समावेशी वातावरण में कार्य करने की दक्षता प्राप्त हो सके। इस समावेशन का क्रिया-प्रणालीगत आधार मजबूत बनाने के लिए शिक्षा संस्थानों का ढांचा और समर्थन प्रणालियाँ सुव्यवस्थित की गई हैं। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, इन पहलों ने व्यावहारिक बाधाओं को भी सामने लाया है, जैसे संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ। प्रभाव का मूल्यांकन अत्यावश्यक होते हुए भी आवश्यक मानकों को स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। जबकि इन पहलों के सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट हैं, कुछ अप्रत्यक्ष परिणाम और व्यवहारिक कठिनाइयां भी देखी गई हैं। इस संदर्भ में, नीति-निर्माण और क्रियान्वयन के लिए सटीक दिशानिर्देश आवश्यक हैं ताकि समावेशी शिक्षा न्यायसंगत एवं प्रभावी हो सके। वैश्विक अनुभवों से सीख लेकर भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में अभिसरण कर सकता है, जिससे समावेशी

शिक्षा का लक्ष्य अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। अंततः, परिवर्तन निरंतर प्रक्रिया है; सतत निगरानी और अनुकूलन से ही इन सुधारों का दूरगामी प्रभाव सुनिश्चित होगा और समाज में समावेश एवं समानता के मूल्य स्थायी रूप से स्थापित होंगे।

9.शोध ग्रंथ सूचि

- Alamelu, N. R., Mary Metilda, R., & Antony, G. (2022). *Continuous up skilling of teaching faculty for competency building: During and post pandemic.*
- Kumar Nag, R. (2022). *Is India ready to accept an EdTech-intensive system in post pandemic times? A strategic analysis of India's "readiness" in terms of basic infrastructural support.*
- Aithal, S., & Aithal, S. (2019). *Analysis of higher education in Indian National Education Policy Proposal 2019 and its implementation challenges.*
- Adhikari, D., Chandra Sharma Poudyal, D., & Rajan Binayek Pasa, D. (2023). *COVID-pandemic in Nepal: An opportunity to institutionalise local governance in school education.*
- Fatima Shirly Anitha, G., & Narasimhan, U. (2021). *Seeing the National Education Policy 2020 through the lens of early child development.*
- Krishnapriya, T. K., & Rani, P. (2022). *The parrot's training in the pandemic: Fallacies in India's educational response to COVID-19.*
- **अलमेलु, एन. आर., मैरी मेटिल्डा, आर., एवं एंटोनी, जी. (2022).** *महामारी के दौरान और बाद में अध्यापक संकाय की दक्षता निर्माण हेतु निरंतर कौशल-वृद्धि पर अध्ययन।*
- **कुमार नाग, रोहित. (2022).** *महामारी के बाद भारत में एड-टेक आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाने की तत्परता: आधारभूत संरचना के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण।*
- **ऐथल, श्रीरामणा., एवं ऐथल, शुभ्रज्योत्स्ना. (2019).** *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधानों एवं उनके कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण।*
- **फातिमा शर्ली अनीथा, जी., एवं नारसिम्हन, उदयकुमार. (2021).** *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बाल्यावस्था विकास के दृष्टिकोण से देखना।*
- **कृष्णप्रिया, टी. के., एवं रानी, पद्मा. (2022).** *महामारी के दौरान भारत की शैक्षिक प्रतिक्रिया में आई विसंगतियाँ: "तोते की ट्रेनिंग" रूपक के माध्यम से विश्लेषण।*

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

SHIKSHA SAMVAD

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87
Volume-02, Issue-02, Dec.- 2024
www.shikshasamvad.com
Certificate Number-Dec-2024/34

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

सुरेन्द्र कुमार

For publication of Book Review title

NEP 2020 के समावेशी शिक्षा सुधार: एक औपचारिक विश्लेषण

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-02, Issue-02, Month December, Year- 2024, Impact-Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.shikshasamvad.com